

# गटए नें दडते भाइत को बचाने वाले शहीदों को ज हजारा ज उनका कोई शोक

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट  
सेक्टर 9 फ़रीदाबाद की कोठियों में  
सफाई करने वाली 26 वर्षीय सरिता के 34  
वर्षीय पति भीम की दशा दिल्ली के गटर  
साफ करने वाले धोंधू बाबुराम, जाखड़  
और धनीराम से बिल्कुल भी अलग नहीं।  
शुरू में तो गटर का ढक्कन खुलते ही उल्टी  
हो जाया करती थी, फिर एक दिन हिम्मत  
कर गटर में उतर ही गए। उनके सर पर  
इंसानी मल का एक हिस्सा आ कर गिरा;  
उसी दिन से उल्टी और घबराहट ने साथ  
छोड़ दिया।

भीम अपने ठेके दार से सुरक्षा उपकरणों की मांग करते थे पर ठेकेदार निगम से कम पैसे मिलने का बहाना बना टाल जाता था। भीम जानते हैं कि निगम से ठेकेदार को 6500/- रुपये पार्ट टाइम कार्मिकों के नाम पर प्रति माह मिलते हैं पर ठेकेदार उसमें से 1500 और कभी 2000 तक रख लेता है। क्योंकि रोजगार की कमी है इसलिए ठेकेदारों के हाथों शोषित होने को मजबूर हैं। अब भीम ने इन सब चीजों की मांग करना बंद कर दिया है। पर हाँ, ठेकेदार से एक देसी दारू की बोतल रोज लेते हैं क्योंकि गटर में उत्तरने की हिम्मत जुटाने के नाम पर पीने वाली दारू अब जिन्दगी का हिस्सा बन गई है।

बीते हफ्ते दिल्ली और गाजियाबाद से सीधर साफ करने उतरे सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौत की खबरें आयीं। एक हफ्ते में 10 लोगों कि मौत वो भी एक ही तरह से। इसमें से 6 मौतें देश की राजधानी में ही हुयीं जहाँ पर सेटिक टैंक में सफाई कर्मी के उत्तरने पर प्रतिबन्ध है। यह दर्शाता है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार भी उसी राह की पथिक है जिसकी भाजपा समेत अन्य सरकारें।

बाबूराम, दिल्ली रंगपुरी पहाड़ी की द्विगियों में 18 वर्ष अपने पिता के साथ बिता चुके हैं। पहले, पिता धोंधू गटर सफाई का काम करते थे अब उनकी जगह बाबूराम जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने गटर सफाई के लिए न दस्ताने दिए न हेल्पमेट और न ही कोई अन्य सुरक्षा उपकरण। शुरू में तो इंसानी मल में सने शरीर की बदबू से खुद खाना भी नहीं खा पाते थे। इतना कुछ करने के बाद भी तय दाम 500 से मोल-भाव कर 400 या कभी कभी 300 तक देते हैं, जो भी दूर कहीं रख कर ताकि बाबूराम का हाथ न छू जाए। शुरू में बुरा लगता था पर फिर आदत पड़ गई।

बाबुराम का पड़ोसी धनीराम बाबुराम के पहले से गटर सफाई का काम कर रहा है। 28 साल की उम्र में एक दिन गटर की गैंस ने उसे लगभग लील लिया था। मोहम्मदपुर गाँव के गटर की सफाई के दौरान अचानक धनीराम का दम घुटने लगा और वो लगभग मरणासन हो चुका था। बाहर बैठे धोधू के अनुभव ने उन्हें बता दिया कि नीचे कुछ अनहोनी है जिस कारण से धनीराम बचा लिए गए। धनीराम की पत्नी उस हादसे के बाद जब भी वो गटर में उतरने जाती है, साथ जाती है। उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मदद के अभाव में वो अन्त मर जाए।

अभाव म वा अन्दर मर जाए।  
जाखड़, आयानगर दिल्ली के वाल्मीकि  
मोहल्ले में रहते हैं। इससे पहले दिल्ली के  
विष्णु नगर में थेकेदार सततीर के मातहत  
गटर सफाई का काम कर रहे थे। जीवन  
के 35 वर्ष से देख चुके जाख ? ने अपने  
बेटे की मौत को इतने करीब से देखा कि  
फिर हिम्मत नहीं हुई सीधर में उतरने की।  
पोपले मुंह से बी गी का कश मुट्ठी भर के  
लेते हुए जाखड़ ने कहा, निगम के पक्षे



गटर में नहीं उतरता, लाखों-करोड़ की पगार का यह झाडू वाला!

सफाईकर्मी अधिकतर खुद सीवर में नहीं उतारते बल्कि हम जैसे कॉर्टेक्ट पर काम करने वालों को ही उतारते हैं। बस दारु का खर्चा करते हैं और अपने अनुभव से कभी कभी बचा लेते हैं हम जैसे मजबूरों को।

जाखड़ ने अपने 18 वर्षीय बेटे सन्नी से मिलवाया और बताया कि एक दिन उनके जगह सन्नी को गठर में उतारने पर वो मरने मरते बचा। ठेकेदार ने ही उनको ऐसा करने को कहा और जब हादसे के बाद खान पूर्ति के लिए निगम अधिकारियों ने पूछताछ की तो ठेकेदार ने आरोप जाखड़ पर हर्ष लगा दिया। इसके बाद आज तक उनकी बची हुई पगार भी नहीं दी और काम तो खेर छूट ही गया। अब वे आया नगर में नालियों की सफाई कर अपना जीवन का रहे हैं।

ऐसी हजारों कहनियाँ इन स्वच्छता के सिपाहियों से सुनी जा सकती हैं पर शायद प्रधानमंत्री मोदी के पास ये कहानी सुनने का समय नहीं। ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने सारे पाप किये हैं बल्कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का पहला कानून देश में 1993 में पारित हुआ और फिर 2013 में इससे सम्बन्धित दूसरा अधिनियम आया इसमें सूखे शौचालयों की सफाई और रेलवे पटरियां साफ करने वालों को भी शामिल किया गया।

2। मार्च 2014 को इसी मुद्रे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस काम में लंगूर श्रमिकों को पुनर्वास योजना के तहत ठीक से बसाया जाए और हाथ से मैला ढाने की प्रथा को समाप्त कर गटर सफाई के लिए जरूरी उपकरण मुहैया कराये जायें। इसके बावजूद सरकरें और निगम सो रहे हैं हादसे होते रहते हैं और सरकारी आंकड़े का हिस्सा बनते रहते हैं।

सफाई कर्मचारी आन्दोलन के आंकड़े  
के अनुसार 1993 से अब तक 1370 सीवियर  
श्रमिकों की जान खतरनाक परिस्थितियों  
के कारण चली गई। इनमें से सिर्फ 480  
के ही रिकार्ड उनके पास पूरे हैं। सुप्रीम  
कोर्ट के आदेशानुसार ऐसे प्रत्येक श्रमिक  
के परिवार को 10 लाख बतौर मुआवज  
मिलना चाहिए, परंतु अब्बल तो मुआवज  
सबको मिला नहीं और जिन गिने चुने लोगों  
को मिला उन्हें भी सिर्फ 3 से 4 लाख।

इस कार्य से जुड़े श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए स्व रोजगार योजना के पहले वर्ष

में 100 करोड़ रुपए कि राशि आवंटित की गई। खास बात ये है कि स्वच्छता का राग गाने वाली भाजपा के शासन ने 2014-15 और 2015-16 में इस योजना पर कही

व्यय ही नहीं किया। 2016-17 के बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और संशोधन कर इसमें भी एक करोड़ की कटौती कर दी गई। इस वर्ष के अनुमान

गटर गैस से चाय नहीं बनती मोदी जी, जान निकलती है

सत्रह सितम्बर को भारत सरकार के निर्देश पर देश भर में प्रधानमन्त्री का जन्म दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। सारा सरकारी अमला इसी में व्यस्त रहा। लेकिन जिन सफाई कर्मियों के कांथों पर यह बोझ डाला हुआ है वे स्वयं शहर की सबसे गंदी बस्तियों में रहने का अभिशप्त होते हैं। उनमें भी गटर सफाई कर्मियों की कार्यदशा रोज उन्हें मौत के मुँह से साक्षात्कार कराने वाली है।

दस अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चाय वाले का जिक्र छेड़ा था। जबकि मीडिया फुटेज ले गई गटर की गैस। इस गैस के बारे में मोदी ने अखबार में पढ़ा था और प्रत्यक्ष रूप से देखा भी था कि इससे बर्नर जल सकता है, चाय बन सकती है, चाय वाले का घर चल सकता है। जब पकड़े से घर चल सकता है तो गटर की गैस से बनी चाय से क्यों नहीं!

खैर देश के यशस्वी पीएम के मुंह से निकलने के बाद गटर वाली गैस ने देश में हाहाकार मचा दिया। व्यंग्य करने वाले सक्रिय हो गए, जब जमलेबाज एक्टिव हैं तो दसरे क्यों नहीं? पर ऐसे मोदी भक्त भी हैं जो मानते हैं कि छेद वाला बर्तन उल्टा कर नाली

लेकिन इस सारे हो हज्जे में गटर वाली गैस की सबसे जरूरी बात रह गई जो मोदी जी ने नहीं बताई। यह गैस, मोदी जी की चाय बना सकती है या नहीं पर इंसानों की जान जस्तर ले सकती है और रोज ले भी रही है। उसकी चपेट में आ कर इंसान वैसे ही मरता है जैसे कोई कीड़ा हिट से छिड़कने पर।

यहाँ उस आदमी की बात हो रही है जो रोजाना किसी न किसी गटर में सफाई के लिए उत्तरता है। यह आदमी पकौड़े नहीं खाता खाता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं बचते और वो चाय भी नहीं पीता क्योंकि उसका काम चाय जितने नशे में चलता नहीं। उसे अपने होशो-हवाश दुरुस्त रखने के लिये दारू, जी हाँ शराब नहीं दारू, पीनी पड़ती है।

वो रोज सुबह दास्त लगा कर काम पर निकलता है और ठीक सड़क के बीच में बने उस लोहे के ढक्कन पर नजर गढ़ता है जिससे आम कार, साइकिल या रिक्शावाला भी बच कर निकल जाते हैं। वो उसे खोल कर किनारे करता है और गटर में बर्टन उल्टा करके डालने के बजाय उसमे पत्थर मारता है। पत्थर मारने के पीछे उसका कम दिमाग होना नहीं है। ऐसा करने से गटर के काकरोच बाहर निकलते हैं। यह आदमी खुश होता है और गटर में उतर जाता है जहाँ उसके जैसे मनुष्यों का मल महीनों से सड़ रहा होता है।

गटर के काकोरीच उस आदमी को इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि जब हम जी रहे हैं तो त भी नहीं मरागा। इस आदमी को जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं हम किसी नाम से नहीं जानते हैं पर यही आदमी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के अग्रिम मोर्चे की सबसे सच्चा सिपाही है, जो सीवर गैस से जान का खतरा होने के बावजूद भी गटर में उतरता है।

रसायनशास्त्री की भाषा में कहें तो सीवर गैस में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो हरेक अपने आप में बेहद हानिकारक हैं। एक तय मात्र से ज्यादा यदि ये गैसें शरीर में चली जायें तो प्राण परखेरु डड़ा सकती हैं।

यूं तो यहां आदमी की सुक्षा के लिए हमारे देश में प्रोहिक्षिण ॲफ एप्मलॉयमेंट ऐज मैन्युअल स्केवेंजर एंड रीहैबिलिटेशन एक्ट 2012 बना हुआ है। इस कानून के तहत घरों में लगे सेप्टिक टैंक, पाइप, गरट, सीवेज प्लाट के टैंक इत्यादि की सफाई के लिए बिना समत्रित सुरक्षा उपकरणों के सफाई कर्मचारी को नहीं उतारा जाएगा। इस कानून को लागू करने की सीधे जिम्मेवारी जिला के डीएम की होती है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में तो मनव्यों को इस तरह की सफाई पर लगाने पर ही रोक है। फिर भी रोज़ इन सफाई सिपाहियों के खच्च भारत अधियान के मोटी मोर्चे पर शहीद होने की खबरें आती रहती हैं।

गटर में उत्तरने वाले सफाई कर्मियों की मौतों का एक ही पैटर्न होता है। पहले एक आदमी गटर में उत्तरता है, फिर जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आता तो उसे बचाना दूसरा उत्तरता है और फिर तीसरा। जब तीनों नहीं आते तब मशीनें लायी जाती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर होता है चुका और गाजियाबाद में घटी बीते दिन की घटनायें इसका सबूत हैं कि कम से कम तीन लोग मरते ही हैं।

ऐसा कर्तर्त नहीं है कि साफ सफाई का जोखिम इस आदमी की जान ले लेता है या इसकी मौत को टाला नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में गटर जाम होते हैं और जब एक सीमा के बाद तकनीक अपने हाथ खड़े कर देती है तो कोई न कोई व्यक्ति उसमें उतरता भी है। भारतवर्ष की तरह वो आदमी किसी खास कौम से नहीं होता। उसकी जिन्दगी कीमती समझी जाती है और वो सारे जरुरी सुरक्षा उपकरणों से लैस होता है। उसे अच्छी प्रगार भी मिलती है और कोई उसे छोटा समझने की हिमाकत नहीं करता।

इस साल अप्रैल में सरकार ने लोकसभा में बयान दे कर बताया कि हाथ से मैला ढोने पर रोक के बावजूद इसी वजह से साल 2017 में 300 से ज्यादा लोगों के मौत हो चुकी हैं। इस हिसाब से एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से साल

को फर्क नहीं पड़ता, न आम को न खास को जबकि मल सबका निकलता ही है। विश्व जैविक दिवस पर भी मोदी जी ने गटर में उतरने वाले इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके भक्तों के हिसाब से पीएम के पास टूसेरे बहुत काम होते हैं। इसके लिए टूसेरे छोटे मंत्री और अफसर हैं। मोदी जी के भक्तों की मानें तो वो रोज 18 घंटे काम करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बेडरूम में, नुकङ्ग पर या कहीं भी चाय पीते हुए आप क्या बात करेंगे ये मोदी जी चुटकी बजा कर तय कर सकते हैं और करते हैं। जैसे योगा डे, सेल्फी विद डॉटर, पकड़े से रोजगार इत्यादि इत्यादि। यदि मोदी जी अपने काम के 18 घंटों में से एक मिनट निकाल कर इन गटर में उतरने वाले लोगों पर भी एक शब्द कह दें तो क्या पata इनके बारे में भी बात होने लगे और देर सबेर प्रशासन भी जागे, जिससे ये कीड़े के माफिक मरने से बच जायें।

में सिर्फ पांच करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। सिर्फ मारे गए लोगों के मुआवजे की बात हो तब भी 120 करोड़ की आवश्यकता है। इन खोखले प्रयासों का ही नतीजा है जो आज तक इस वर्ग के लोग बेमौत मरने के लिए मजबूत हैं और डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत का ढोंग रखने वाले मोदी जी को गटर की गैस से चाय बनाने की कहानी सुनाना याद है पर गैस से मरने वालों की सुध लेना नहीं।

पंद्रह सितम्बर को मोदी ने फिर से अपने नाट्य अभिनय का जलवा बिखेरते हुए भक्तों को सफाई के नाम से साफ सड़क पर झाड़ू का कोमल स्वर्ण करा मंत्रमुद्ध कर दिया। राष्ट्रीय अखबारों ने उनके द्युक कर एक तिनका उठाने का बेहतरीन क्लोजअप शॉट मुख्य पृष्ठ पर छापा। ऐसा ही सुपरहिट ड्रामा मोदी ने 2014 में राजघाट जैसी साफ जगह से प्रारंभ किया था। तब से लेकर अब तक कितनी सफाई हुई? और उससे भी बढ़ा सवाल ये है कि सफाई का असल जिम्मा जिनके कन्धों पर डाल मोदी सरकार मीडिया में छा जाना चाहती है उनकी हालत में क्या सुधार किया?